

Fourteenth Loksabha**Session : 10****Date : 07-05-2007****Participants : [Rawat Prof. Rasa Singh](#)**

>

Title: Need to set up a separate Pay Commission for Armed Forces.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश के सशस्त्र बलों को विद्रोही गतिविधियों, आतंकवाद, भीतरी तथा बाहरी खतरों से निरंतर जूझना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सैनिकों को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया जाता है। पिछले पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से सशस्त्र बलों के लिए कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं, जिनमें ब्रिगेडियर को मेजर जनरल से अधिक पेंशन देने की सिफारिश शामिल है। इतना ही नहीं, सैनिक की सेवानिवृत्ति पर केन्द्र सरकार के चपरासी की आधी पेंशन की सिफारिश की थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन विसंगतियों के कारण सेना, जल सेना में और वायु सेना में योग्य अधिकारी नहीं आ रहे हैं। सैनिकों की भर्ती भी अपेक्षाकृत कम हो रही है और हजारों पद खाली हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सशस्त्र सेनाओं के लिए छठा वेतन आयोग अलग से गठित किया जाए। अभी जो वेतन आयोग गठित किया गया है, उसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए उनके साथ अन्याय होने की संभावना है। अतः विसंगतियों को दूर करने और सशस्त्र सेनाओं को न्याय देने के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए। धन्यवाद।